Sl. No.	Name of factory	Location
32.	Shri Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.	Datta Nagar
33.	Shree Warna Sahakari Sakhar Karkhana	Kolhapur
34.	Vidarbha Paper Mills Ltd.	Nagpur
35.	Central India Spinning Weaving & Mfg. Co. Ltd.	Nagpur
36.	Jayakwadi Pulp & Paper Mills Ltd.	Nagpur
37.	Nagpur Paper Mills Pvt. Ltd.	Nagpur
38.	Gaurav Paper Mills	Nagpur
39.	JBA Printing Ink (P) Ltd.	Hingna Road
40.	The Paper Products Ltd.	Hingna Indl Est.
41.	Shree Kakshmi Narayan Paper Mills (P) Ltd.	Nanded
42.	Shikusa Paper (P) Ltd.	Nasik
43.	Shree Vindhya Paper Mills Ltd.	Panchak
44.	Deccan Paper Mills Co. Ltd.	Mundhwa
45.	Pudumjee Pulp & Paper Mills Ltd	Poona
46.	F. Pudumjee & Co. Pvt. Ltd.	Poona
47.	Kasat Paper & Pulp (P) Ltd.	Pune
48.	Indor Afrigue Paper Mills.	Pune
49.	Parashuram Paper & Boards Mfg. Co. Ltd.	Ratnagiri
50.	Shirkee Paper Mills Pvt. Ltd.	Satara
51.	Nira Pulp & Paper Mills Ltd.	Satara
52.	Kay Pulp & Paper Mills Ltd.	
53.	Siddeshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.	Solapur
54.	Ajanta Paper & Genl Prods (P) Ltd.	Thana
55.	Laxmi Board & Paper Mills Pvt. Ltd.	Kalyan
56.	B.K. Paper Mills Pvt. Ltd.	Thana
57.	Balkrishna Paper Mills Ltd.	Thana
58.	IPCO Paper Mills Ltd.	Thana
59.	Keelkama Paper Pvt. Ltd.	Thana
60.	The Paper Products Ltd.	LBS Marg
61.	Ballarpur Industries Ltd.	Gadchiroli

Balanced industrial development in the country

3856. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the steps Government propose to take for bringing about the balanced industrial development in the country;

(b) whether foreign industrialists intending to establish industries in the country would be asked to establish the industries in interior and rural areas of the country;

(c) if so, whether Government feel that there would be disenchantment and desertion among the people living in the backward and under developed area of the country; and

(d) whether Government are aware that this would lead to fissiparous tendencies among the people?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (d) Under the liberalised regime, industries are free to choose the area of location. However, Government provides fiscal concessions and infrastructure support for locating industries in backward areas. In hilly and inaccessible areas Government also provides transport subsidy for raw materials and finished goods.

Industrialisation of Gujarat

3857. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) in what ways the Central Government are supporting and supplementing the efforts being made by Government of Gujarat for industrialisation of the State particularly in its no industries districts and blocks;

(b) the details thereof;

(c) whether funds have been earmarked for the State for this purpose; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (d) The Ministry of Industry, Department of Industrial Policy & Promotion is presently operating the Growth Centre Scheme, 1988. Under the Scheme, the State of Gujarat has been allotted and approved

three growth centres at Gandhidham (Kutch), Palanpur (Banasakantha) and Vagra (Bharuch). The Central Government's contribution to each approved centre is Rs. 10 crores. Central assistance is released having regard to the physical and financial progress in the implementation of the Growth Centre.

Under the Integrated Infrastructural Development (IID) Scheme, 1994, Gujarat has been sanctioned one centre in village Miyani, district Junagarh with a project cost of Rs. 5 crores.

मध्य प्रदेश में खादी और कुटीर उद्योगों के विकास हेतु योजनाएं

3858. **श्री अजीत जोगी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में खादी और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ग) किन-किन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि की सहायता दी गई?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मध्य प्रदेश सहित देश में खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। इसके सामान्य कार्यक्रमों के अलावा, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने मध्य प्रदेश के 15 खंडों में 125 खंड विकास कार्यक्रम तथा राज्य के 6 जिलों में जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रम भी शुरू किये हैं।

(ख) और (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वित्तीय सहायता के अलावा, खादी तथा पोलीवस्त्र कार्यक्रम के लिए ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाणपत्र के आधार पर संस्थागत वित्तीय अभिकरणों के जरिये भी धनराशि मुहैया की जाती है जिसके तहत कार्यान्वयन अभिकरण 4% वार्षिक की दर से ब्याज वहन करते हैं और इसके व बैंक दर के बीच के अंतर की पूर्ति खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजसहायता के रूप में की जाती है। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तैयार तथा प्रस्तुत की गयी परियोजनाओं के आधार पर कंसोर्टियम बैंक ऋण के अंतर्गत भी धनराशि मुहैया की जाती है। परियोजना प्रस्ताव के अंतर्गत 10.00 लाख रु० तक की लागत वाली परियोजना शुरू में बिना ब्याज के 25% सीमांत धन के लिए पात्र होते हैं जो ऋण की पुनर्अदायगी के बाद अनुदान में बदल जाता है। 10.00 लाख रु० से अधिक और 25.00 लाख रु० तक लागत वाली परियोजनाएं प्रथम 10.00 लाख रु० के लिए 25% की दर से और शेष राशि के लिए 10% की दर से सीमांत धन की पात्र होती हैं। पर्वतीय/सीमावर्ती, जनजाति तथा कमजोर वर्ग वाले क्षेत्र, अ०ज०/अ०ज०ज०/अ०पि०व०/अल्प संख्यक/सेमफैक्स-3/महिला लाभ भोगियों के मामलों में, 10.00 लाख रु० तक की परियोजनाएं 30% की दर से सीमांत धन के लिए पात्र हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए कुल वितरित राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(रुपये लाख में)

वर्ष	अनुदान	ऋण
1994-95	203.23	497.36
1995-96	112.07	303.23
1996-97	41.11	455.49

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी की गई उपर्युक्त राशि के अलावा, सरकार की गारंटी पर बैंक कंसोर्टियम द्वारा स्वीकृत ऋण से के०वी०आई० सी० द्वारा मध्य प्रदेश को 1995-96 के दौरान 891.81 लाख रु० की राशि भी प्रदान की गई थी।

विभिन्न उद्योगों को राजसहायता का प्रावधान

3859. **श्री अजीत जोगी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न उद्योगों को राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद उद्यमियों को कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना हेतु कोई अनुदान भी प्रदान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान इस संबंध में मध्य प्रदेश के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा कितनी राशि दी गई; और

(ङ) सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए औद्योगिक इकाइयां लगाये जाने हेतु कौन-कौन सी नई योजनाएं बनाए जाने का विचार है?